ONGC and the second for inter-city transportation. The third for tourist charters. The fourth linking accessible areas in hilly terrains subject to the availability of infrastructure and economic viability of the operation.

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: Sir, I would like to know from the Minister whether the helicopter service would be considered from Palam to Connaught Place to cut down on the time, because Connaught Place is a wide....

SOME HONOURABLE MEMBERS: Parliament House will be better.

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: It is close enough to Connaught Place. The point is that in most cities of the world, city services are available. It might be good to think of this service from Palam to Connaught Place and back.

SHRI JAGDISH TYTLER: At present we have no proposal. In future if need be, we will consider it.

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति-महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया है है कि ओ०एन०जी०सी० कुछ हेलिकोप्टरों का इस्तेमाल कर रही है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि जो विदेशी हेलिकोप्टर ब्रिटिश हेलिकोप्टर है, रूस के हेलिकोप्टर हैं या दूसरे हैं उनके क्या मूल्य हैं?

SHRI JAGDISH TYTLER: This question relates to ONGC.

श्री गुलाम रसूल कार : मैं मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है उसके पार्ट सी में मुख्तलफ स्टेजेज पर आपने आफर दिये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके पहले आफर देने से पहले गवर्नमेंट के सामने जब यह स्कीम है तो क्या गवर्नमेंट ने कोई सर्वे किया है रूट्स का, इसके लिए क्या कोई जगहें मुतखब की हैं ?

[شری غلام رسول کار.. میں منتری جی نے جو جواب دیا ہے اسکے پارٹ سی میں مختلف اسٹیجز پر ایپ آفر دیئے ہیں- میں یہ جاننا چاہتا ہوں اسکے پہلے آفر دینے سے پہلے گورنمنٹ کے سامنے جب یہ سکیم ہے تو کیا گورنمنٹ نے کوئی سروے کیا ہے روٹس کا- اس لئے کیا کوئی جگہیں منتخب کی ہیں-]

SHRI JAGDISH TYTLER: The question of surveying does not arise.

..Unemployment of the Ayurvedic.. Graduates

*422. SHRI PYARELAL KHANDELWAL:‡

SHRI LAL K. ADVANI:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) what is the number of unemployed Ayurvedic graduates at the end of each of the last three years and at present and the reasons of their being without proper employment; and

(b) what is the annual turnover from the Ayurvedic colleges and what steps Government are taking for their absorption?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) and (b) As per information available at the end of 1982, 1983 and 1984, graduates in Ayurveda numbering 6721, 6874 and 8057 respectively were on the live Registers of the Employment Exchanges in India. The out-turn of

†[‡Transliteration in arabis. script.

‡The question was actually asked on the floor of the House by Shri Pyarelal Khandelwal.

graduates from Ayurvedic Colleges every year is approximately 2000.

The State Governments are primarily concerned for providing Health care services and thus generating opportunities for the absorption of these graduates in Government services and otherwise. Most of the State Governments have established Ayurvedic Dispensaries/Hospitals and Teaching Institutions. The Central Government has also established Ayurvedic C.G.H.S. Dispensaries, Hospitals and National level Teaching Institutions|Research Council.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : सभापति जी, सरकार ने जो उत्तर दिया है उसमें आयुर्वेदिक डाक्टरों की संख्या जो रोजगार कार्यालयों में दर्ज है वह 1982 में 6721 1983 में 6874 और 1984 में 8057 बताई है। इसका मतलब है कि प्रति वर्ष बेरोजगार आयुर्वेदिक डाक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रति वर्ष 2 हजार स्नातक उत्तीर्ण आयुर्वेदिक डाक्टर तैयार किये जाते हैं। अगर 1984 के आंकड़े हम देखें तो 4 वर्ष में जितने आयुर्वेदिक डाक्टर तैयार हुए है उतनी ही संख्या 1984 में आयुर्वेदिक बेकार डाक्टरों की है जो बेरोजगार कार्यालय में दर्ज किये गये हैं। इसका मतलब यह है कि आयुर्वेदिक डाक्टरों को काम देने की सरकार के पास एक व्यवस्थित योजना नहीं है, इसलिए बेरोजगार डाक्टरों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है, इतना ही नहीं सरकार का ऐलोपैथिक के मुकाबले आयुर्वेदिक पद्धति और आयुर्वेदिक डाक्टरो के साथ भेदभाव का भी रवैया रहा है, आयुर्वेदिक डाक्टरों के वेतनमान और एलोपैथिक डाक्टरों के वेतनमान में भी अंतर है इतना ही नहीं . . .

MR. CHAIRMAN: Now put your question.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : सिविल सर्जन के प्रमाणपत्र को मान्यता है मैं पूछ रहा हूं प्रश्न पर आ रहा हूं। लेकिन आयुर्वेदिक डाक्टर के प्रमाणपत्र को सरकार मान्यता नहीं देती है। पहला प्रश्न मेरा यह है कि क्या सरकार आयुर्वेद के डाक्टरों के वेतनमान और एलोपैथिक डाक्टरों के वेतनमानों में समानता लायेगी और दोनों को एक समान वेतन दिये जायेंगे ?

SHRI KRISHNA KUMAR: Sir, there are 2½ lakh Ayurvedic practitioners in the country and the number registered in the Employment Exchanges is only of the order of 8,000 or less than 2½ per cent. In the National Health Policy, one of the cardinal thrust we have given is expansion of the Indian systems of medicine. The infrastructure is steadily expanding. I do not want to give the figures here, but it is not the obligation of the Government to give Government employment to all the graduates coming out of the Ayurvedic institutions. Sir, we have 1,500 hospitals, 1,000 dispensaries, graduate training colleges, postgraduate institutions. CGHS dispensaries and so on.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : मैंने तो वेतनमान का पूछा है।

SHRI KRISHNA KUMAR: In the Seventh Plan, the expenditure is a hundred times more for the Indian systems of medicine than in the First Plan. The Government does not have any proposal at the moment for parity between the pay-scales of Allopathic and Ayurvedic medical practitioners. The Hon. Member mentioned something about the degrees. There have been clear guidelines on the basis of which degrees are recognised as valid. The Central Council of Indian System of Medicine have laid down the standards, and as per the Indian Systems of Medicine Act, and the Schedule thereunder the institutions which have been recognised have been included. Certain degrees which are now being given in certain States of the country are not recognised by the Government.

MR. CHAIRMAN: Second supplementary.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : मेरे दूसरे भाग का जवाब नहीं मिला है। मैंने पूछा था कि सिविल सर्जनों के सर्टिफिकेट के अनुसार आयुर्वेदिक डाक्टरों के सर्टिफिकेट को भी क्या सरकार मान्यता देगी। इसका जवाब नहीं मिला है, मैं चाहता हूं कि वह जवाब मिल जाये।

मेरा दूसरा सवाल यह है कि छठी योजना के मुकाबले सातवीं योजना में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में कितने आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना बनायी गयी है और सातवीं योजना में कितने बेरोजगार डाक्टरों को काम देने का व्यवस्था सरकार ने की है?

मेरे प्रश्न के तीन भाग हैं- सर्टिफिकेट वाला, बेरोजगार डाक्टरों को सातवीं पंचवर्षीय योजना में काम देने वाला और केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कितने आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जाएंगे?

SHRI KRISHNA KUMAR: Every year 1000 to 1200 ayurvedic graduates are absorbed in the Government services at the current rate of absorption. We have set apart Rs. 20 crores for the development of ayurved. It is divided into several schemes, Centrally sponsored and Centrally assisted schemes. These include upgradation of the departments of ayurvedic colleges, and includes opening new dispensaries and hospitals. I would require notice to give the exact number of institutions which will be completed during the Seventh Plan.

MR. CHAIRMAN: He also asked about certain certificates issued by the ayurved medical practitioners being not accepted by the Government. What is the position?

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल कितने अस्पताल खोले जाएंगे? नम्बर नहीं बताया।

SHRI KRISHNA KUMAR: I require notice to be able to give the exact number. As regards the other question, I may be able to answer it if the Hon. member tells me what type of certificates he has in mind.

MR. CHAIRMAN: All right, the Member will write a letter to you. Next. Mr. L. K. Arvani.

श्री लालकृष्ण आडवाणी : सभापति जी, यह सवाल कुल मिलाकर नीति का है कि केन्द्रीय सरकार का दृष्टिकोण क्या है आयुर्वेदिक स्नातकों के बारे में? जो आकड़े दिए हैं, उसमें यह स्पष्ट है कि 2000 स्नातक प्रतिवर्ष अगर निकलते हैं, तो उसमें 1000 या 1200 हो कुल मिलाकर एब्जार्ब होते है सारे देश में यह ठीक है कि जहां तक राज्य सरकारों का सवाल है, उनके अपने अस्पताल है, लेकिन जो सी० जी० एच०एस० के अपना व्यवस्था है दिल्ली से बाहर, उसमें आयुर्वेदिक स्नातकों के लिए कितनी गुजाइश है और राज्य सरकारों को कभी केन्द्र की ओर से इसके बारे में हिदायत दी गयी है या दी जाने वाली है कि आयुर्वेदिक स्नातकों को एब्जार्ब किया जाये, उनको प्रोत्साहित किया जाये।

श्रीमती मोहसिना किदवई : सभापति जी नीति की बात माननीय सदस्य ने कही है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो फिगर्स मेरे साथी ने दी है, वे लाइवरजिस्टर से ली है। यह कोई जरूरी नहीं है कि जो 8 हजार की फिगर है, इनको नौकरी न मिली हो या कोई काम न कर रहे हों। अक्सर लोग यह करते हैं कि नाम अपना लिखवा देते हैं, नौकरी तो करते है लेकिन अच्छी नौकरी के सिलसिले में अपना नाम नहीं कटवाते हैं या कहीं प्राइवेट प्रेक्टिस ये लोग कर रहे होते हैं। सरकार की पालिसी है कि इंडियन सिस्टम आफ मेडिसिन को बढ़ाया जाये और इसीलिये ही, जैसा माननीय मेम्बर को मालूम है कि चार कौन्सिल अलग-अलग बनाई गयी है और उन कौन्सिल के जरिए कोशिश हो रही है कि और ज्यादा स्ट्रेन्थन किया जाये, पैसा भी ज्यादा एन्थकेट किया जा रहा है उबेलो फाइव ईयर प्लान में इनको इम्प्लाय करने के लिए जहां कुछ चीजें जो मेरे कुलीग ने अभी बताई, इसके अलावा जितने हमारे

प्राइमरी हेल्थ सेन्टर है सेंटर की तरफ से यह गाइडलाइन स्टेट को दी गयी है और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि जो तीसरा डाक्टर हम हर पी०एच०सी० में दे रहे है.या रखना चाहते हैं वह वैद्य हो या हकीम, उसको प्रेफर करें उसको रखें औ. जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से डिस्पेंसरी है, उसमें भी काफी, इस वक्त ए ग्जेक्ट फिग. तो नहीं दे सकते कि कितनी डिस्पेंसरी है लेकिन आयुर्वेदिक की डिस्पेंसरी हैं।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : दिल्ली से बाहर सी०जी०एच०एस० में भी ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : जी हां।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय : सभापति जी, कृपया मंत्री जी बताएं कि इस वक्त देश में कुल कितने आयुर्वेदिक कालेज है और अगले पांच वर्षों में 1985-1990 के बीच में कितने नए आयुर्वेदिक कालेज शुरू करने का प्रस्ताव सरकार की ओर से है?

SHRI KRISHNA KUMAR: Sir, there are 100 ayurvedic colleges in the country. We do not have a decision at the moment to open any new colleges.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : एक सवाल तो सभापति जी, यह है कि पंचवर्षीय योजना में आपने बीस सौ करोड़ रुपये के प्रावधान की बात कही है लेकिन में समझता हूं कि 70 करोड़ की आबादी में जो ग्रामीण अंचल है, जहां पर आयुर्वेद सिस्टम से ही इलाज किए जाते हैं, यह प्रावधान बड़ा ही कम है, इसलिए सप्तम योजना के तहत यह विकास काम नहीं हो सकेगा । एक तो यह विचार करने के लिए मेरा निवेदन है।

दूसरे, जो माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि प्रत्येक—यह जनता पार्टी की रिजीम में ही हो चुकी थी—कि प्रत्येक विकास प्रखण्ड में तीसरा डाक्टर आयुर्वेद का या भारतीय चिकित्सा पद्धति का होगा, लेकिन मंत्री जी यह बतायें कि इसका आज तक कितना पालन हो सका है? जब तक इसका पालन नहीं होगा, तब तक यह सिद्धांत रूप में रहेगा।

इसी का एक सन्दर्भ और आपकी नजर में लाना चाहता हूं कि आयुर्वेद सिस्टम की दवाइयों का प्रचार युरोपियन, रशियन कण्ट्रीज में प्रचुर मात्रा में बढ़ रहा है और वहां पर इसके विकास का बहुत प्रयास किया जा रहा है।

मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय रिसर्च, जो आयुर्वेदिक का है, उसमें अभी तक कितने रुपये लगाये है और आगे पंचवर्षीय योजना में कितना रुपये लगा करके इसको विकसित करना चाहते हैं?

आज जो अमरीका या रूस हमको पीछे छोड़ना चाहते हैं आयुर्वेद सिस्टम में, उसके मैचिंग में आप कैसे मुकाबला करेंगे और आज दुनिया में जिस तरह एलोपैथिक डाक्टरों की मांग बढ़ रही है, आज आयुर्वेद डाक्टरों की भी मांग, खास करके युरोपियन कण्ट्रीज में बहुत हो रही है, उसके लिए भी क्या आपकी कोई योजना है?

MR. CHAIRMAN: All right. Your time is up. Yes. Mr. Minister.

SHRI KRISHNA KUMAR: Sir, the figure of Rs. 20 crores which I mentioned represents the Central allocation in the Seventh Five Year plan. In addition, the States will be spending about Rs. 80 crores for the development of Ayurveda during the Seventh Plan period.

Sir. the importance of developing the Indian systems of medicine has been emphasised in our National Health Policy. We are having a three-pronged thrust: firstly, the development of infrastructure, secondly, development of the integrated system between the indigenous and modern systems of medicine and, thirdly. attention to preventive, promotives. and public health aspects of primary health care. In all these areas. we are going to give emphasis to the Indian systems of medi-

cine. In the First Plan, the total allocation was Rs. 40 lakhs only. Now, Sir, it is hundred times more or Rs. 40 crores for the ISM in the Central sector.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : थर्ड डाक्टर का क्या किया है ?

SHRI KRISHNA KUMAR: Sir, the Government order on the posting of the third doctor from among the ISM disciplines in the Primary Health Centres in the country is still extant. Some of the States have implemented it and some of the States have not implemented it. We are steadily pursuing the matter with the States. This is a State subject. We are trying to implement it.

श्री बापू कालदाते : सभापति महोदय, अब यह बात सब लोग मान रहे हैं कि माडर्न मेडिसिन में बहुत सारे साईड इफैक्टस होते हैं।

इसके दो कारण है, एक तो बगैर जाने हुए कोई भी बीमारी हो जाए, तो ब्राड स्प्रेक्टम एंटिबायटिक्स जिसका कुछ असर होता है, इसको न देखते हुए भी इन दवाइयों का इस्तेमाल इस देश में होता है और लोग इस बात पर आ चुके हैं कि अगर ठीक ढंग से सोचें तो जो आयुर्वेद या जो हिंदुस्तानी, भारतीय पद्धति है, उसका उपयोग बगैर साईड इफैक्टस के किया जा सकता है ।

इसके लिए सरकार का ध्यान इस तरफ अगर गया हो कि जितने इस पद्धति को विकसित करना चाहिए एक तरफ से ।

दूसरी तरफ हम देखते है कि राज्यों में—जिस राज्य से मैं खुद आता हूं, उस राज्य में जहां प्राइमरी हैल्थ सेंटर्ज पर पहले आयुर्वेद के डाक्टर रखे जाते थे। उसमें से उन लोगों को अब रखना बंद कर दिया है । वह तो मेरी खुद की जानकारी, है, विधायक के नाते जब में था उस विधान सभा में, तो कई लोगों को निकाला गया था।

आप कहते हैं कि आपने गाईडलाइंस दी हैं। हम यह चाहते हैं कि इसकी रिसर्च ज्यादा, अच्छे ढंग से करने के लिए इस पर ज्यादा जोर देने के लिए तथा साथ ही साथ जो गाईडलाइंस दी है तीसरे चिकित्सक के लिए, तो इस तीसरे आदमी को भारतीय पद्धति का ही होगा, इसको इम्पलिमेंट करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं?

SHRI KRISHNA KUMAR: We have already sated that we are pursuing with the State Governments to implement the order. As regards the side-effects of allopathic drugs, the issue is governed by the Drugs and Cosmetics Act and the rules made thereunder. We agree with the honourable Member's proposition that the indigenous systems of medicine should be given the maximum encouragement by the Central Government and the States.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : सभापति महोदय, इनको जवाब देना चाहिए कि यह इम्पलिमेंट नहीं हो रहा है।

MR. CHAIRMAN: Next Question. Question No. 424.

*423. [*Transferred to the 20th December, 1985*].

Import of High Technology

*424. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Railways have currently formulated any plan to import high technology from Japan and other countries for improving high speed passenger trains. and existing railway Workshops, and maintenance and operation of freight; and

(b) if so, which are the major areas identified for high technology development to improve the technology used for maintaining the existing fleet of locos and coaches?